(घ) इस समय राज्य-वार किन-किन जिलों में छिड़काव (ड्रिप) सिंचाई योजना चल रही है और चालू वित्तीय वर्ष में यह किन-किन जिलों में कार्यान्वित होने जा रही है; और

(ङ) शुष्क सिंचाई योजना किन-किन क्षेत्रों में चल रही है तथा चालू वित्तीय वर्ष में इसे किन-किन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाना है?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख) आठवीं योजना के शुरू में निर्माणाधीन वृहद, मध्यम और विस्तार नवीकरण/आधुनिकीकरण योजनाओं का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है (देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र संख्या 102)

(ग) विद्यमान नीति के अनुसार, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन और वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट सम्बन्धी संसाधनों से स्वयं किया जाता है तथा उन्को केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है जो विकास के किसी क्षेत्र या किसी परियोजना से संबंधित नहीं होती है। योजना आयोग ने वर्ष 1994-95 के लिए योजना के तहत 416.73 करोड रुपए की मांग की एवज में इस मंत्रालय को 275.47 करोड रुपए की राशि आबंटित की है तथा वित्त मंत्रालय ने गैर योजना के अंतर्गत 120.66 करोड रुपए की मांग की एवज में 95.16 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है।

(घ) देश में 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने के लिए आठवीं योजना में ड्रिप सिंचाई की केंद्रीय प्रायोजित योजना के वास्ते 197.10 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध किया गया है। यह योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कियान्वित की जा रही है।

(ङ) "शुष्क सिंचाई योजना" नाम की कोई केंद्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय योजना नहीं है।

Dumping of stored water of dams in Maharashtra into sea

5196. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that stored water from the dams at Koyna, Chandoli and Kallanwadi in Maharashtra is dumped into the sea and into various rivers since irrigation canals have not been constructed, hence making the water unavailable for farmers; and

(b) if so, what steps Government intend to take to expedite the construction of canals so that the stored water of these dams can be utilised for agricultural purposes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) (a) and(b) While the Koyna Dam was completed long back, Warna dam near village Chandoli is scheduled for completion in 1994. The canal system of Warna project is scheduled to spill over beyond VIII Plan. The Project authorities have planned to release water in the Left Bank Canal for irrigation of 1,000 hectares in its initial reaches. 19.90 Thousand Million Cubic Feet of water is also proposed to be released into the river for irrigation of 50,500 hectares through lift irrigation. The Union Government is not aware of Kallanwadi dam in Maharashtra. Koyna Krishna Lift Irrigation Project, an Ongoing Major Project envisages to utilise water from Krishna river during monsoon period and from Koyna dam during non monsoon period. The project is scheduled to spill over beyond VIII Plan.

लघु सिंचाई योजनाएं

5197. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने लघु सिंचाई योजनाओं के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया है और यह राशि वर्ष 1992-93 के दौरान दी गई राशि से कितनी कम या अधिक है;

(ख) क्या सरकार ने लघु सिंचाई योजना को लोकप्रिय बनाने तथा उसका विकास करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना से प्रतिवर्ष कितने एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो कृषि में सिंचाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके लिए पर्याप्त प्रबंध करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) चालू वित्तीय वर्ष (1994-95) के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को योजनागत निधियों के तहत उपलब्ध कराई गई राशि 2559.22 करोड़ रुपए है । वर्ष 1992-93 के दौरान उपलब्ध की गई 1743.73 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में यह राशि 47% अधिक है ।

(ख) से (घ) लघु सिंचाई योजनाओं के विकास के लिए 10.711 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने के वास्ते आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अधिक परिव्यय उपलब्ध किया गया है अर्थात् 5977.26 करोड़ रुपए योजनागत परिव्यय तथा 5119 करोड़ रुपए संस्थागत निवेश । सृजित की गई/सृजित की जाने वाली वर्ष-वार अनन्तिम क्षमता निम्न प्रकार है :

1992-93

1.70 मिलियन हेक्टेयर (वास्तविक)

1993-94

1.39 मिलियन हेक्टेयर (प्रत्याशित)

1994-95

1.90 मिलियन हेक्टेयर (लक्ष्य)

केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित की गई विभिन्न योजनाओं अर्थात् बागवानी फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली; सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम; मरुस्थल विकास कार्यक्रम आदि के अंतर्गत वित्तीय सहायता का प्रावधान करके लघु सिंचाई योजनाओं को लोकप्रिय बनाया जा रहा है तथा इनका विकास भी किया जा रहा है ।

Water requirement of Delhi

5198. SHRI RAM NATH KOVIND : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) what is the total requirement of water consumption of Delhi;

(b) what is the availability of water through various sources to meet the requirement ;

(c) whether Government of NCT of Delhi submitted proposals for meeting deficit requirement from other States, if so, what is the Central Government's reaction thereto and what is the present status of its action plan, if any ; and

(d) whether it is a fact that Minister for Water Resources intervened in the water dispute between Delhi and Haryana and whether the dispute has been resolved for all the times to come ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) According to Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking, Delhi requires about 700 million gallon per day (MGD) of water to meet the drinking water as well as other requirements for the present population including floating population.

(b) About 550 MGD of water is being produced at present by optimisation of Water Treatment Plants in Delhi. Raw water is made available from various sources like surplus Ravi-Beas waters, Yamuna waters, Ramganga waters and ground water.

(c) Delhi Government had requested Union Government to persuade Haryana Government to supply additional raw water to Delhi to meet the deficit. The Union Government has been requesting Haryana Government to supply additional water to Delhi whenever such a shortage